ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

भारत नेपाल सम्बन्ध : वर्तमान परिदृश्य

डॉ. राम अवतार राम

एसोसिएट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

सारांश

भारत और नेपाल के मध्य सम्बन्ध अनादि काल से हैं। दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं, इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। स्वतन्त्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष सम्बन्धों को 1950 के भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि के द्वारा नयी ऊर्जा दी। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल मैत्री और सहयोग के अद्वितीय सम्बन्ध रखते हैं, जिसमें खुली सीमाओं और जनता के बीच रिश्ते और नातेदारी व संस्कृति के सम्पर्कों का गहरा सम्बन्ध है।

भारत-नेपाल के मध्य ***शान्ति एवं मैत्री की सन्धि (1950)*** से, भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट सम्बन्धों की शुरुआत को आधार प्राप्त हुआ। इस सन्धि के प्रावधानों के अन्तर्गत नेपाली नागरिकों ने भारतीय नागरिकों के समान भारत में सुविधाओं और अवसरों का अभूतपूर्व लाभ उठाया है। वर्तमान में लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं।

भारत और नेपाल के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर चलता रहता है तथा यात्राएँ भी नियमित रूप से होती रहती हैं। नेपाली प्रधानमन्त्री श्रीमान सुशील कोइराला 26 मई, 2014 को प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने भारत आये थे। अगस्त 2014 में प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल की यात्रा की तथा नवम्बर में दक्षेस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाल की यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये । भारत और नेपाल के पास, **भारत-नेपाल संयुक्त आयोग** सहित कई द्विपक्षीय संस्थागत संवाद तन्त्र हैं। जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मन्त्री और नेपाल के विदेश मन्त्री करते हैं। जब 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.4 तीव्रता का भूकम्प आया, तब भारत सरकार ने नेपाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल और राहत सामग्री सहित विशेष विमान को नेपाल के बचाव के लिये भेजा।

नवम्बर 2005 में, दिल्ली में सात दलों के गठबन्धन और माओवादियों के बीच 12-बिन्दु की सहमति से भारत सरकार ने शान्तिपूर्ण समाधान और समावेशी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए नवम्बर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शान्ति समझौते द्वारा निर्धारित रूपरेखा का स्वागत किया है। शान्ति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने तथा विधिवत निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाने के माध्यम से तथा बहुदलीय लोकतन्त्र के संस्थाकरण के रूप में भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार की आवश्यकताओं के प्रति लगातार समर्थन किया है। भारत ने सदैव यह माना है कि सभी पक्षधारकों पर बोर्ड द्वारा व्यापक सहमति से केवल एक समावेशी संविधान ही नेपाल में स्थायी शान्ति और स्थिरता पैदा करेगा।

नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने 20 सितम्बर, 2015 को मधेशियों तथा अन्य दलों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक संविधान का प्रख्यापित किया था। भारत सरकार ने चल रहे विरोधियों के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है और नेपाल सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक विश्वसनीय राजनीतिक वार्ता के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने के प्रयास करे।

परिचय

1996 से भारत को नेपाल का निर्यात 11 गुना से अधिक और द्विपक्षीय व्यापार में सात गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 1995-96 में नेपाल के कुल बाहरी व्यापार के 29.8% का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2013-14 में 66% पहुँच गया। नेपाल से भारत का निर्यात वर्ष 1995-96 में 230 करोड़ अमरीकी डालर से बढ़कर 2013-14 में 37.135 अरब रुपये हो गया और वर्ष 1995-96 के दौरान भारत का निर्यात 15.25 अरब रुपये से बढ़कर 2013-14 में ₹2.95456 खरब (4.81 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया। **भारत से नेपाल को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएँ हैं:-** पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और कलपुर्जे, गर्म रोंटियाँ, तार, कोयला, सीमेंट, धागे और रसायन।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

नेपाल से भारत को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएँ हैं:- पॉलिएस्टर का धागा, जूट का सामान, धागा, जड़ाई शीट, पैकेज्ड जूस, इलायची, पाइप, जूते और सैण्डल, पत्थर और रेत।

नेपाल की कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 38.3% हिस्सा भारतीय उपक्रमों का है। 15 जुलाई, 2013 तक नेपाल सरकार ने 72.694 अरब रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कुल 3004 विदेशी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। नेपाल में लगभग 150 भारतीय उपक्रम हैं जो निर्माण, सेवा (बैंकिंग, बीमा, शुष्क पत्तन, शिक्षा और दूरसंचार), विद्युत क्षेत्र और पर्यटन उद्योग में रत हैं। कुछ बड़े भारतीय निवेशकों में आई टी सी, डाबर इण्डिया, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, सी. टी. सी. एल. एल, एमटीएनएल, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, एशियन पेंट्स, जिनर इण्डिया, बीआईटी ग्रुप होल्डिंग, बीआईटी ग्रुप होल्डिंग, नुपुर इन्टरनेशनल, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप, पटेल इंजीनियरिंग, भीलई एन्टरनेशनल, ट्रांसवर्ल्ड ग्रुप, पेटेल इंजिनियरिंग, भीलई, भुषड़ पेन्ट्स, जेसएक्स इंफ़्रा प्रोजेक्ट लि. और टाटा पावर आदि शामिल हैं।[1]

नेपाल के वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी ओली नें प्रधानमन्त्री पद संभालकर सबसे पहले भारत का दौरा किया।[4] उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और भी मजबूत हुए हैं। जब 2015 में नेपाल में भूकम्प आया था। तब भारत ने तुरन्त प्रतिक्रिया देते हुए भारत से राहत सामग्री एवं NDRF के जवान सहायता के लिये भेजे थे। इसी तरह भारत हर समय नेपाल की सहायता करता रहा है।

भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा तनाव 2015 में मधेशियो का विरोध से बढ़ा है। मधेशी, वहाँ के तराई क्षेत्र में रहने वाले रहने वाले लोग हैं। जब 2015 में नया संविधान बना तो वहाँ पर संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गयी कि थारू, मधेशी और जनजाति लोगों को नेपाली संसद में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व कम मिला और नेपाली (पहाड़ी) लोगों को अधिक मिला जिसके चलते मधेशियो ने 2015 में भारत नेपाल सीमा पर सड़क जाम किया, जिससे भारत से नेपाल जाने वाले समान की आवागमन बन्द हो गया और नेपाल ने भारत पर आरोप लगाया कि आन्दोलन भारत समर्थित है।

अभी हाल में नेपाल द्वारा अपनी मानचित्र में लीपुलेख का क्षेत्र अपनी मानचित्र में शामिल किया है जो भारत और नेपाल के बीच वर्तमान विवाद का मुख्य कारण है।

भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि (Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship) भारत और नेपाल के बीच में ३१ जुलाई १९५० में काठमांडु में हस्ताक्षरित करी गई एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि है जिस के अन्तर्गत दोनों देशों के सम्बन्ध निर्धारित करे गए हैं। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा एक-दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी और उन्हें एक-दूसरे के देशों में बिना रोकटोक रहने और काम करने की अनुमति होगी। यह सन्धि दोनों देशों के बीच एक गहरा मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करती है।[2]

विचार – विमर्श

भारतीय नेपाली या **भारतीय गोरखा** वह लोग हैं जो नेपाली मूल के लोग हैं लेकिन भारत में रहते आ रहें हैं, जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त है। वह लोग नेपाली भाषा के अलावा भी कई भाषाएं बोलते हैं, नेपाली भाषा भारत के कार्यालयी भाषाओं में से एक है, इतिहास में नेपाल अधिराज्य के वह भाग जो ब्रिटिश राज के समय भारत में आ गये जैसे, पश्चिम बंगाल का दार्जीलिंग जिला जो सिक्किम का भू-भाग था और कुछ समय के लिए नेपाल का भी भू-भाग रहा, सिक्किम-एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ मुख्य रूप से नेपाली रहते हैं जो 1975 में भारत का हिस्सा बना। दूसरे राज्य जहाँ नेपालीयों कि बहुलता है वह हैं :- उत्तराखण्ड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। भारत के कई बड़े शहरों में भी नेपालीयों कि बहुलता पाई जाती है, मुख्यत: दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और विशाखापटनम। **भारतीय मूल के नेपाली** या **भारतीय नेपाली** नेपाल के उन नागरिकों को कहते हैं जिनका आंशिक या पूर्ण विरासत भारतीय है। उदाहरण के लिए, मधेशी लोग भारतीय नेपाली हैं। वर्तमान समय में भारत से विस्थापित बहुत से लोग नेपाल के नागरिक हैं जिनकी संख्या ५० से ६० लाख तक होने का अनुमान है।

भूगोल एवं इतिहास की अनिवार्यताओं के परिणामस्वरूप दोनों पड़ौसियों की आर्थिक नियति का अंतर्गुम्फन हुआ है। नेपाल के विदेश व्यापार का दो तिहाई भारत के साथ होता है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार अनुमानत: लगभग 4.7 बिलियन डॉलर का है। नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 47 प्रतिशत भारत से है। 1996 में संशोधित व्यापार संधि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

की केंद्र बिंदु साबित हुई है। 1996 के बाद से, भारत में नेपाल के निर्यात में ग्यारह गुणा वृद्धि हुई है और द्विपक्षीय व्यापार सात गुणा से अधिक बढ़ गया है। भारतीय फर्में नेपाल में सबसे बड़ी निवेशक हैं जिन्होंने कुल अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का लगभग 40 प्रतिशत निवेश किया है। नेपाल में लगभग 150 से अधिक भारतीय उपक्रम कार्य कर रहे हैं जिनमें विनिर्माण, सेवाओं (बैंकिंग, बीमा, शुष्क बंदरगाह, शिक्षा और दूरसंचार), ऊर्जा क्षेत्र एवं पर्यटन उद्योग जैसे विविध क्षेत्रों के उपक्रम शामिल हैं। नेपाल में निवेशकर्ताओं में अन्य के साथ-साथ आईटीसी, डाबर इंडिया, टाटा पावर, हिंदुस्तान यूनीलिवर, वीएसएनएल, टीसीआईएल, एमटीएनएल, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और एशियन पेंट्स शामिल हैं।

बहु-स्तरीय संबंधों की इस पृष्ठभूमि में, भारत की विदेश मंत्री 26 जुलाई को काठमाण्डू में अपने नेपाली काउंटरपार्ट महेंद्र बहादुर पाण्डे के साथ संयुक्त आयोग की अध्यक्षता करेंगी। बैठक का महत्व इसी बात से पता चल सकता है कि 23 वर्षों में यह प्रथम संयुक्त मिशन होगा और इसमें i) राजनैतिक, सुरक्षा एवं सीमा संबंधी मुद्दे, ii) आर्थिक सहयोग एवं अवसंरचना, iii) व्यापार एवं ट्रांजिट, iv) ऊर्जा एवं जल संसाधन, v) संस्कृति, शिक्षा एवं मीडिया संबंधी मुद्दों के पांच क्षेत्र शामिल होंगे। वार्ता के महत्व की ओर इशारा करते हुए और बैठक में चर्चा के व्यापक स्वरूप के मुद्दों के चलते, विदेश, ऊर्जा, जल संसाधन, वाणिज्य, सड़क परिवहन, रेलवे, मानव संसाधन विकास, संस्कृति मंत्रालयों के अधिकारी मंत्री के साथ रहेंगे। संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करने के साथ-साथ, मंत्री महोदया नेपाल के राष्ट्रपति राम बरन यादव, प्रधान मंत्री सुशील कुमार कोइराला और नेपाल के संपूर्ण परिदृश्य में राजनैतिक नेतृत्व के साथ भी बैठक करेंगी।[3]

संयुक्त आयोग के क्षेत्र के चलते, कोई भी सहजता से यह कह सकता है कि वार्ता के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी। 1950 की शांति एवं मित्रता संधि, जो भारत-नेपाल संबंधों का मूल सिद्धांत हैं, में संशोधन के मुद्दों पर भी चर्चा के दौरान बात की जाएगी। इस संधि को नेपाली राजनीतिक संस्थापन के एक वर्ग द्वारा अवैध माना जाता है, परंतु भारत ऐसा नहीं मानता है, फिर भी नई दिल्ली ने संकेत किया है कि वह नेपाली पक्ष से प्राप्त होने वाले ठोस सुझावों को स्वीकार करने का इच्छुक है।

सुरक्षा को बढ़ाना और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करना भारत की अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इस संदर्भ में, दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां विस्तृत क्षेत्रों में अतिसक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं, जिसमें गैर कानूनी स्मगलिंग, हथियारों की तश्करी और नकली मुद्रा के मुद्दे शामिल हैं। खुली सीमाओं और भारत नेपाल सीमाओं को आतंकवादियों द्वारा वाहक के रूप में उपयोग किए जाने की रिपोर्टों के चलते, आने वाले दिनों में संबंधों के सुरक्षा आयाम को अवश्य सहारा प्राप्त होगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जलविद्युत सहयोग की क्षमता का लाभ प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो अलग-अलग मान्यताओं के कारण बहुत अधिक अछूता रहा है। वार्ता से भारत को उम्मीद है कि एक नया ऊर्जा करार संभव होगा जो इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद अवसरों के नए द्वारा खोलेगा। यदि करार हो जाता है तो, यह नेपाल में बार-बार पैदा हो जाने वाले ऊर्जा संकट का समाधान करेगा, और भारत भी करार के भाग के रूप में अतिरिक्त बिजली प्राप्त करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, नेपाल में 40,000 मेगा वॉट हाइडल पावर है जो तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाई गई है। कुल हाइडल क्षमता 80,000 मेगा वॉट होने का अनुमान लगाया गया है। यदि नेपाल की जल-विद्युत क्षमता का अभीष्ट दोहन किया जाए, तो यह दक्षिण एशिया का सबसे संपन्न देश बनने की क्षमता रखता है।

आशय

विकास भागीदारी के क्षेत्र को विस्तृत करना वह अन्य मूहत्वपूर्ण क्षेत्र होगा जिस पर वार्ता के दौरान बल दिया जाएगा। भारत ने इस हिमालयन राज्य के समावेशी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को अनेक बार रेखांकित किया है और नेपाल सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो आर्थिक ऋण पहले ही प्रदान कर दिए हैं।

विकास भागीदारी व्यापक क्षेत्रों में हुई है, इनमें भारत राजमार्गों, पुलों, ऑप्टिकल फाइबर लिंकों, मेडिकल कॉलेजों, ट्रॉमा सेंटरों, पॉलीटेक्नीकों, स्कूलों, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कर रहा है। नदी प्रशिक्षण एवं तटबंध विनिर्माण के लिए, भारत सरकार ने उदारता से निधियां और विशेषज्ञ सहायता प्रदान की है ताकि लालबकेया, बागमती और कमला नदियों के

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

तटबंधों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार हो सके। इसके अलावा, विद्युत पारेषण लाइनों के स्तरोन्नयन के लिए एक 250 डॉलर का और दूसरा 125 डॉलर का एक्सिम बैंक ऋण प्रदान किया गया है। नेपाल के विभिन्न जिलों में चल रही लगभग 450 लघु विकास परियोजनाओं ने साधारण नेपाली जनता के लिए खुशियों का संसार बनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन का कहना है- "इनमें से कई परियोजनाओं की सफलता की कहानियां उल्लेखनीय हैं। जब हमने घेंघा परियोजना को शुरू किया था, तब उसे नेपाल को घेंघा से मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था। 1985 में नेपाल में घेंघा लगभग 44 प्रतिशत लोगों को हो जाता था। वर्ष 2007 में जब हमने इस परियोजना को समाप्त किया तब यह आंकड़ा घट कर 0.4 प्रतिशत रह गया।" प्रशिक्षण के क्षेत्र में, भारत द्वारा 3000 नेपालियों को वार्षिक रूप से छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

संयुक्त आयोग की बैठक नेपाल के राजनैतिक पटल पर बदलाव के मध्य तब होने जा रही है जब संविधान-निर्माण की प्रक्रिया नया स्वरूप ले रही है। भारत ने नेपाल के आंतरिक मामलों से स्वयं को अलग रखने की सुविचारित नीति को बनाये रखा है, परंतु हिमालयन राज्य में, जो आधुनिकता और राष्ट्रीय नवीकरण की अपनी यात्रा को स्वयं की शर्तों पर तय कर रहा है, चिर शांति और स्थायित्व लाने के लिए एक समावेशी राजनैतिक प्रक्रिया की निरंतर रूप से मैत्री भाव से वकालत की है। 27 मई को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री कोइराला के साथ अपनी बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को "एक पुराने और बहुत ही सम्मानित मित्र" के रूप में वर्णित किया और ईमानदारी से उम्मीद जताई कि नेपाल द्वारा संविधान को एक वर्ष की उस समय-सीमा में अंगीकार कर लिया जाएगा जो उसने अपने लिए तय की है।[4]

अत: भारत की विदेश मंत्री की 25-27 जुलाई की यात्रा प्रचुर संभावनाओं से प्रदीप्त है और यह भारत के प्रधान मंत्री की शीघ्र ही होने वाली महत्वपूर्ण काठमाण्डू यात्रा के लिए आधार तैयार कर सकेगी। प्रधान मंत्री का दौरा, जब भी होगा, भारत-नेपाल संबंधों को नए मार्ग पर लाने और दोनों पक्षों के लिए बहुआयामी लाभदायक अवसरों के असंख्य नए द्वार खोलने के लिए निर्णायक पल साबित हो सकता है, जिससे दोनों पड़ौसी देश खुशहाली के लिए मिलकर काम करते हुए और अधिक निकट आएंगे।

परिणाम

नेपाल में आम चुनाव होने के बाद साम्यवादी दल की सरकार सत्तारूढ़ हुई और के पी शर्मा ओली 15 फरवरी 2018 को प्रधानमन्त्री पद पर आसीन हुए. इसके बाद भारत और नेपाल के बीच आपसी यात्रायें हुई और कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इसमें दोनों देशों के मध्य सहयोग, कनेक्टिविटी, आपसी विश्वास और लोगों के मध्य आपसी संपर्क को बढाने में काफी मदद मिली है. विगत वर्षों में एक दूसरे राष्ट्र का महत्व समझते हुए, एक तरफ जहाँ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक नेपाल की चार बार यात्रा की वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने अपने दोनों कार्यकालों में भारत को राजकीय यात्रा के लिए प्रथम वरीयता दी. संभवतया, साल 2015 में नए संविधान की घोषणा और अघोषित नाकाबंदी के बाद दोनों देशों के मध्य संबंधों में आए ठहराव और अविश्वास को समाप्त करने का दोनों पक्षों की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया. इसके साथ साथ दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अतिरिक्त बहुपक्षीय मंचों की सार्थकता समझते हुए क्षेत्रीय स्तर पर भी सहयोग को आगे बढाया है. इस लेख में पिछले एक साल में दोनों देशों के मध्य हुई पारस्परिक यात्राओं के महत्व और इस दौरान हुए समझौतों का वर्णन है. नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली 6 से 8 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहे. विगत वर्ष हुए संघीय और प्रांतीय स्तर के चुनावों में अप्रत्याशित जीत के बाद ही यह निश्चित हो गया था कि एमाले के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमन्त्री होंगे. वर्ष 2015 में बने नेपाल के नए संविधान के लागु करने की प्रक्रिया को पूरा करते हुए ओली 15 फरवरी 2018 को प्रधानमन्त्री पद पर आसीन हुए. ओली के प्रधानमन्त्री बनने के एक सप्ताह के भीतर भारत के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और भारत आने का न्योता भी दिया. ओली की प्रधानमन्त्री के रूप में यह भारत की दूसरी यात्रा थी इससे पहले वह मार्च 2016 में भारत आए थे. इस यात्रा से पूर्व के दो घटनाक्रमों को देखना यहाँ जरुरी है. पहला, काफी समय बाद नेपाल के ऐसे प्रधानमन्त्री भारत आए जो कि आम चुनाव द्वारा निर्वाचित हैं, एक स्थिर सरकार के मुखिया हैं और संसद में उन्हें बहुमत प्राप्त है. दूसरा, मार्च महीने में पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खाकान अब्बासी के नेपाल दौरे के बाद नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व पर भारत यात्रा का एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए. रेल लिंक समझौता: रक्सौल से काठमांडू तक- भारत और नेपाल के प्रधानमन्त्री एक नई विधुतीकरण रेल लाइन के निर्माण पर सहमत हुए, जिसमे भारत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा. यह रेल लाइन भारत के सीमावर्ती शहर रक्सौल

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ेगी. भारत सरकार इसके लिए नेपाल सरकार से विमर्श करेगी और एक साल में इसका प्राथमिक सर्वे का काम पूरा होगा. दोनों पक्ष इस प्रोजेक्ट के लागू होने का अंतिम फैसला विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने पर करेंगे.

दूसरा महत्वपूर्ण समझौता नेपाल को जलमार्ग से समुद्र तक रास्ता देना है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने सागरमाथा को सागर से जोड़ने की बात कही है. दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस पर सहमति प्रकट करते हुए कहा कि व्यापार और पारगमन की व्यवस्थाओं के तहत नेपाल को अतिरिक्त रूप से समुद्री मार्ग मिलेगा और कार्गो और ट्रकों की सुगम आवाजाही होगी. इस पर दोनों नेताओं ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी सहमति के आधार पर इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया का सूत्रीकरण किया जाए.[5]

तीसरा समझौता कृषि क्षेत्र में नई साझेदारी को लेकर हुआ. दोनों देशों के किसानों, उपभोक्ताओं, वैज्ञानिक समुदाय और निजी सेक्टर के पारस्परिक लाभ के आधार पर बने ज्ञापन समझौते के तहत कृषि विज्ञान और तकनीक तथा कृषि उत्पादन और कृषि प्रक्रिया में सहयोग को शामिल किया गया है. यह साझेदारी कृषि अनुसन्धान और विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति की संयुक्त परियोजनाओं पर केन्द्रित होगी. इसके तहत बीज तकनीक, मृदा गुणवत्ता, मूलनिवासियों की पीढ़ियों के संसाधन, कृषि-वन जैविकता, जैव उर्वरकता आदि पर अनुसन्धान शामिल है.

वस्तुतः नेपाल के प्रधानमन्त्री ओली की इस यात्रा में समझौतों से अधिक आपसी विश्वास के निर्माण पर बल दिया गया. इस यात्रा के दौरान नेपाल का राजनीतिक नेतृत्व एक नई राजनीतिक व्यवस्था और एक नई सोच के साथ भारत से अपने रिश्ते आगे बढ़ाने के मकसद को प्रकट करने के प्रयास करते दिखा. मोदी और ओली की बैठक के दौरान नेपाल के प्रधानमन्त्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे लिए संधि समझौतों से पहले अपनी मित्रता है, जिसका समर्थन प्रधानमन्त्री मोदी ने भी किया और उन्होंने कहा कि हम भी यही चाहते है कि आपसी विश्वास बढे और मित्रता मजबूत हो. इस यात्रा के भारत ने सार्क के इतर बिम्सटेक और बी बी आई एन जैसी उप क्षेत्रीय संगठनों में साझेदारी के संकेत दिए. चीन की ओबोर परियोजना और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल में कनेक्टिविटी की बात करना कही ना कही नेपाल को पाकिस्तान और चीन के हमराही के रूप में दिखाता है. लेकिन भारत ने नेपाल की स्थल-बद्धता को जानते हुए इस बार रेलमार्ग और जलमार्ग जैसे संपर्कों से नेपाल को कनेक्टिविटी देने की पहल की. कुछ विश्लेषक इसे वर्ष 2016 में नेपाल चीन के मध्य हुए रेल मार्ग समझौते का प्रत्युत्तर मानते है. यहाँ तक कि संयुक्त वक्तव्य में भारत के प्रधानमन्त्री मोदी द्वारा सागरमाथा से सागर तक जोड़ने की बात इसको पूर्ण रूप से सिद्ध करती है.

अप्रैल माह में नेपाल के प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली की भारत यात्रा के बाद प्रधानमन्त्री मोदी की नेपाल यात्रा को एक त्वरित पारस्परिक यात्रा के तौर पर देखा जा सकता है. 11 और 12 मई की यह दो दिवसीय राजकीय यात्रा भारतीय प्रधानमन्त्री के धार्मिक भ्रमण के अतिरिक्त नेपाली जनता से मुखातिब होने की झलक प्रस्तुत करती प्रतीत हुई. इस यात्रा में भारतीय प्रधानमन्त्री काठमांडू के अतिरिक्त नवगठित प्रान्त-2 की राजधानी जनकपुर गए जो कि इस यात्रा को महज राजनीतिक नेतृत्व की बैठक और संवाद के अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल के स्थनीय स्तर से संवाद करने का अवसर प्रदान करता है. इस यात्रा में प्रधानमन्त्री मोदी का जानकी मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर जाना सांस्कृतिक कूटनीति के तहत दोनों देशों के आपसी मेल मिलाप को बढाने और रिश्तों को प्रगाढ़ करने की दिशा में प्रयत्न को प्रदर्शित करता है.[6]

प्रधानमन्त्री मोदी ने अपनी नेपाल यात्रा जनकपुर से शुरू की, उनका वहाँ स्वागत नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने किया, प्रान्त-2 में उनके नागरिक अभिनन्दन समाहरोह के कारण अवकाश घोषित किया गया. प्रधानमन्त्री मोदी ने इस अवसर पर अपना अभिभाषण नेपाली मैथिली और हिंदी भाषा में दिया. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल दो देश है, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है. राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था. यह बंधन है राम-सीता का, यह बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी और यही बंधन रामेश्वरम में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर आता है. यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बौद्ध-गया ले जाता है और यही बंधन, यही आस्था, यही स्नेह आज मुझे जनकपुर खींच ले आया है. हमारी माता भी एक-हमारी आस्था भी एक; हमारी प्रकृति भी एक-हमारी संस्कृति भी एक; हमारा पथ भी एक और हमारी प्रार्थना भी एक. हमारे परिश्रम की महक भी है और हमारे पराक्रम की गूंज भी है. हमारी दृष्टि भी समान और हमारी सृष्टि भी समान है. हमारे सुख भी समान और हमारी चुनौतियां भी समान हैं. हमारी आशा भी समान, हमारी आकांक्षा भी समान है. हमारी चाह भी समान और हमारी राह भी समान है. ..... हमारे मन, हमारे मंसूबे और हमारी मंजिल एक ही है. यह उन कर्मवीरों की भूमि है जिनके योगदान से भारत की विकास गाथा में और गति आती है. उन्होंने कहा कि 'व्यक्ति और सरकारें आती जाती रहती है लेकिन सदियों पुराने हमारे सम्बन्ध

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

हमेशा मजबूत रहेंगे'. धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अयोध्या जानकी के बिना अधूरा है तथा भारत के तीर्थ स्थान और राम नेपाल के बिना अपूर्ण है. नेपाल के विकास हेतु प्रधानमन्त्री मोदी ने नेपाल सरकार को सहायता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई. उन्होंने प्रान्त-2 के लिए 1 बिलियन (भारतीय) रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की, जिससे कि जनकपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जा सके. इस अवसर पर प्रधानमन्त्री मोदी ने कहा कि 'मैं यह अनुदान सवा सौ करोड़ भारतीयों की तरफ से माता जानकी के चरणों में भेंट करता हूँ'. इस बात को नेपाली मीडिया ने नाटकीय रूप बताते हुए वर्ष 2015 में हुई अघोषित नाकाबंदी की क्षमा के रूप में बताया.[3] उन्होंने आगे कहा कि इतिहास साक्षी रहा है कि जब-जब एक-दूसरे पर संकट आए, भारत और नेपाल, दोनों मिलकर खड़े हुए. हमने हर मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे का साथ दिया है. भारत दशकों से नेपाल के विकास का एक स्थाई साझेदार है. नेपाल हमारी पडोसी पहले की नीति में सबसे आगे आता है, सबसे पहले आता है. हम हिमालय पर्वत से जुड़े हैं, तराई के खेत-खलिहानों से जुड़े हैं, अनगिनत कच्चे-पक्के रास्तों से जुड़े हैं. छोटी-बड़ी दर्जनों नदियों से जुड़े हुए हैं और हम अपनी खुली सीमा से भी जुड़े हुए हैं. लेकिन आज के युग में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है. हमें, और मुख्यमंत्री जी ने जितने विषय बताए, मैं बहुत संक्षिप्त में समाप्त कर दूंगा। हमें हाइवे से जुड़ना है, हमें information ways यानी I-ways से जुड़ना है, हमें trans ways यानी बिजली की लाइन से भी जुड़ना है, हमें रेलवे से भी जुड़ना है, हमें custom check post से भी जुड़ना है, हमें हवाई सेवा के विस्तार से भी जुड़ना है. हमें inland water ways से भी जुड़ना है, जलमार्गों से भी जुड़ना है. जल हो, थल हो, नभ हो या अंतरिक्ष हो, हमें आपस में जुड़ना है. जनता के बीच के रिश्ते-नाते फलें-फूलें और मजबूत हों, इसके लिए connectivity अहम है. यही कारण है कि भारत और नेपाल के बीच connectivity को हम प्राथमिकता दे रहे हैं.

इस यात्रा के दूसरे दिन काठमांडू में जारी हुए संयुक्त वक्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण कदमों को शामिल किया गया, जिसके तहत एक साल में रक्सौल-काठमांडू रेल सेवा के सर्वे को पूरा करने की बात कही गयी. संयुक्त वक्तव्य के अनुसार दोनों देशों के प्रधानमन्त्री इस बात पर भी राजी हुए कि अप्रैल माह में नेपाल के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौतों और आपस में बनी समझ के मुताबिक सभी कार्यों को प्रभावशील तरीके से लागू किया जाएगा. इस बात पर भी सहमति बनी कि कृषि, रेल लिंक और जलमार्गों के विकास की द्विपक्षीय पहल को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाए जिससे कि पूरे क्षेत्र में विकासात्मक परिवर्तन लाया जा सके. इस अवसर पर प्रधानमन्त्री ओली ने भारत नेपाल के मध्य व्यापार और पारगमन पर चिंता व्यक्त की और इसकी समस्याओं और समाधानों पर भी बात कही. दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी की बात पर भी बल दिया और कहा कि इससे आर्थिक उन्नति और आपस में जनता का संपर्क भी बढ़ेगा.

नेपाल में इस यात्रा के मिश्रित भाव रहे, एक वर्ग यह मानता है कि दोनों देशों के मध्य पिछले कुछ समय में उत्पन्न हुए अविश्वास को इस यात्रा ने सफलतापूर्वक ख़त्म कर दिया है. वही दूसरा वर्ग मानता है कि इस यात्रा से प्रधानमन्त्री मोदी ने स्वयं की छवि, अपनी सरकार छवि को नेपाल की जनता समक्ष सुधारने तथा भारत में अपने राजनीतिक समकक्षों और पडौसी देशों की नजरों में भी छवि सुधारने की कोशिश की है. एक वर्ग यह भी मानता है कि इस यात्रा से नेपाल सरकार द्वारा भारत का तुष्टीकरण (अनावश्यक रूप से अभिनन्दन समाहरोह द्वारा खुश करने) करने का भी प्रयास किया गया

संभवत: अन्य किसी दो पड़ौसियों के बीच इतने घनिष्ठ और अंतरंग संबंध नहीं हैं, इनकी जड़ें अतीत में हैं और हजारों अलग-अलग तरीकों से दैनंदिन अस्तित्व में उजागर होते हैं। तथ्य और आंकड़े अपनी कहानी कहते हैं, और व्यापार तथा निवेश, संस्कृति तथा सुदृढ़ व्यक्तिगत संपर्कों से बने संबंधों की एक नयनाभिराम चित्र यवनिका सामने लाते हैं। [7]भारतीय और नेपाली इतनी सहजता से अनायास घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के देश में मुश्किल से ही विदेशी के रूप में देखा जाता है। भारत में छह मिलियन नेपाली काम कर रहे हैं और ऐसे 600,000 भारतीय हैं जिन्होंने नेपाल को अपना घर बना लिया है। नेपाली भारत में बिना किसी कार्य परमिट के काम कर सकते हैं, बैंक खाता खेल सकते हैं और अपनी संपत्ति रख सकते हैं।

मुक्त सीमा ने दोनों देशों के बीच लोगों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, देनों देशों के बीच प्रति सप्ताह 60 उड़ानें होती हैं। नेपाल जाने वाले सभी पर्यटकों में बीस प्रतिशत भारतीय होते हैं, और नेपाल जाने वाले पर्यटकों में से लगभग 40 प्रतिशत भारत होते हुए जाते हैं।

ISSN(Online): 2319-8753
ISSN (Print) : 2347-6710

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology

(A High Impact Factor, Monthly, Peer Reviewed Journal)

Visit: www.ijirset.com

Vol. 9, Issue 3, March 2020

निष्कर्ष

काठमांडू में 30-31 अगस्त को चौथा बिम्सटेक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमे प्रधानमन्त्री मोदी ने शिरकत की और वस्तुतः इस प्रकार उनकी यह नेपाल की चौथी यात्रा हो गयी. भारत के अलावा इस सम्मलेन में अन्य सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों ने भी भाग लिया. जिसमे सभी नेताओं ने क्षेत्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी पर बल दिया. उद्घाटन सत्र में नेपाल के प्रधानमन्त्री ओली ने कहा कि बिम्सटेक से एक ऐसे जोड़ने वाले क्षेत्रीय समूह का विकास हुआ है; जो कि जुड़े हुए देशों, जुड़े हुए समाजों और जुड़े हुए लोगों का संगठन बन कर उभरा है. ओली ने इस अवसर पर यह भी कहा कि हम सभी को इस क्षेत्र में आतंकवाद, संगठित अपराध, मादक और मानव तस्करी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए. इसके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि बिम्सटेक को दक्षेस का विकल्प नहीं समझा जाये. इस दौरान भारत के प्रधानमन्त्री मोदी ने कहा कि भारत अपने नेशनल नोलेज नेटवर्क से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहता है.

इस प्रकार भारत ने बिम्सटेक और अन्य उपक्षेत्रीय संगठन जैसे बी बी आई एन को प्रोन्नत कर नेपाल के साथ रिश्ते न केवल प्रगाढ़ किये है बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर इन स्थल-बद्ध देशों को कनेक्टिविटी के अवसर प्रदान किये है.[8]

भारत नेपाल के मध्य आपसी यात्राओं की कड़ी में 6 सितम्बर को नेपाल के पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दहाल ने भारत की यात्रा की. इस दौरान उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय हितों और विकास के मुद्दों पर बातचीत की. इसी कड़ी में 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की जनकपुर की यात्रा सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करेगी. विगत समय में नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव और निवेश के बावजूद, भारत और नेपाल दोनों देशों के मध्य पारस्परिक यात्राओं में नियमितता से संबंधों में विश्वास, स्थिरता और प्रगाढ़ता को मजबूत करने का प्रयास किया है. लेकिन भविष्य में दोनों देशों के संबंधों की प्रगाढ़ता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इन यात्राओं के दौरान हुए कनेक्टिविटी के समझौतों का क्रियान्वयन समय से पूरा हो पाता है कि नहीं.

यह एक ऐसी यात्रा है जो सदियों पुराने भारत-नेपाल संबंधों में नए क्षितिज की तलाश करने में नया मार्ग प्रशस्त करने वाली साबित हो सकती है। दक्षिण एशिया में एक पड़ोसी देश की अपनी अकेले दूसरी यात्रा के रूप में, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 25 से 27 जुलाई तक काठमाण्डू का दौरा करेंगी, जो एक महत्वपूर्ण यात्रा है और भूगोल, प्रकृति, इतिहास और संस्कृति के गहरे रिश्तों में बंधे दो भ्रातासम पड़ौसियों के बीच एक नए अध्याय की शुरूआत करने की उम्मीद जगाती है। यह यात्रा नई दिल्ली की नई सरकार की विदेश नीति में दक्षिण एशिया की प्राथमिकता को पुन: रेखांकित करती है और यह यात्रा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने शपथ-ग्रहण समारोह के लिए सार्क देशों के नेताओं की मेजबानी किए जाने के लगभग दो माह बाद और श्रीमती सुषमा स्वराज के ढाका की यात्रा किए जाने के एक माह बाद होने जा रही है।[9]

संदर्भ

1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2020.
2. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2020.
3. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 अप्रैल 2020.
4. ↑ https://hindi.theindianwire.com/नेपाली-प्रधानमंत्री-भारत-दौरा-31694/ Archived 2018-04-09 at the Wayback Machine द इण्डियन वायर 2020
5. भारत-नेपाल संबंध 2021
6. भारत-नेपाल सम्बन्ध 2021
7. भारत और नेपाल : समस्त एशिया के लिए एक पुल (रेडियो रूस) 2019
8. "कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी" (हिमालिनी) 2020
9. नेपाल—भारत सम्बन्ध (डॉ निर्मलमणि अधिकारी) 2020